श्री यशपाल सिंह : एग्रीकल्टर के मुताल्लिक जितनी मालूमात हिन्दुस्तान में अब तक हासिल हो सकी हैं, उन को अमल में लाने के लिए तो सरकर के पास साधन नहीं हैं । इस वक्त फारन एक्सचेंज की कमी है । तो इस कमी के होते हुए सरकार को इस बात की क्या जरुरत महसूस हुई कि वह आफ़िसर्ज को नई ट्रेनिंग के लिए बाहर भेजे ?

डा० राम सुभग सिंह : कोई सरकारी या गैर-सरकारी कार्य एक लकीर पर रोकने से देश का कल्याण नहीं होगा । खेती के विस्तार के लिए जितनी जानकारी या बुद्धि उपलब्ध है, उस को कार्यान्वित करने के लिए सरकार को धनाभाव नहीं है । माननीय सदस्य ने विदेशी मुद्रा की बात उठाई है । इस ट्रेनिंग के सम्बन्ध में विदेशी मुद्रा की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि एजेन्सी फ़ार इन्टेरनैशनल डेवेलपमेंट की ओर स इन लोगों के वहां जाने की व्यवस्था की गई है ।

श्री ओंकार लाल बेरवा : मैं जानना चाहूंगा कि जिन देशों में हमारे विशेषज्ञों को कृषि का काम सीखने के लिए भेजा जाता है, क्या वहां की जमीन हमारे यहां की जमीन से इस तरह मेल खाती है कि जिस के आधार पर उन को यह काम सिखाया जाता है ?

डा० राम सुभग सिंह : बहुतेरी बातें हैं, जिन की मेल न खाने के बावजूद भी जरूरत होती है । उदाहरण के लिए अगर राजस्थान में ट्यूबवैल लगाने का प्रश्न है, तो यह जरूरी नहीं है कि इंजीनियरिंग का वह विद्वान, जिस ने रूसर अमरीका या ब्रिटेन में शिक्षा प्राप्त की है, राजस्थान में डैज़र्ट होने के बावजूद वहां पर ट्यूबवैल नहीं लगा सकेगा ।

Motor Vehicle Taxes

*1215. **Dr. L. M Singhvi:** Will the Minister of **Transport** be pleased to state:

(a) the steps taken to secure uniformity and rational simplification in the pattern of collection of motor vehicles taxation;

(b) whether the State Governments have indicated any measure of agreement in this matter; and

(c) if so, what is being done in pursuance thereof?

The Minister of Shipping in the Ministry of Transport (Shri Raj Bahadur): (a) to (c). A statement giving the information required is laid on the Table of the House. [Placed in Library, *see* No. L .T.—2790/64.]

Dr. L. M. Singhvi: May I know whether Government have made any further efforts in respect of the implementation of the principle of single-point taxation on transport vehicles and the principle of the abolition of octroi which was accepted by the Government of India earlier?

Shri Raj Bahadur: So far as single-point taxation is concerned, it is of two types: one is between two States and the other is between more than two States. So far as the tax as between two States is concerned, all the States have agreed in regard to the principle of the single-point taxation. It has been implemented also except in the case of Madras and Mysore wherein it is under negotiation. So far as the other type is concerned, as I have indicated, there is a study group appointed; it is going to advise in regard to the method and the manner in which this tax will be realised on the basis of single-point taxation. About octroi, that is also a matter which has been taken up with the State Governments.

Dr. L. M. Singhvi: May I know whether the Government is making any effort to rationalise and reduce the taxes on motor vehicles in this country and to make them uniform all over the country and, if so, what is the result of that effort?

Shri Raj Bahadur: That is exactly the question which I have answered in the two-page statement. That is what we are doing.

Dr. L. M. Singhvi: There is no mention, Sir, in this statement in respect of rationalisation and reduction of this tax....

Mr. Speaker: I will allow him another opportunity. Let him resume his seat now.

Shri Kapur Singh: May I know whether the Government are aware of any historical or contemporary parrellel to this collection of motor vehicles tax, except, of course, the *jeziya*, the main purpose of which is to humiliate rather than to collect revenues?

Shri Raj Bahadur: I do not think this question can be accepted that way. I completely repudiate this insinuation or suggestion made. This is a legitimate tax for getting revenues.

Shri Jashvant Mehta: It has been said in the statement that the Government of India have been trying to persuade the State Governments to agree to a ceiling on motor vehicles taxation at 75 per cent of the prevailling rates in Madras State. May I know how many States have accepted this formula?

Shri Raj Bahadur: As I have said, the single-point taxation is between two States, and it has been accepted by all States and has been implemented except in the case of two or three South Indian States.

श्री तुलशीदास जाधव : स्टेट गवर्नमेंट्स को जो चार बातें स्वीकार करने के लिये कहा गया है, जिन का जिक्र इस स्टेटमेंट में किया गया है, किन स्टेट गवर्नमेंट्स ने उन को स्वीकार कर लिया है और जिन स्टेट गवर्नमेंट्स ने उन को स्वीकार नहीं किया है, उन्होंने इस सम्बन्ध में क्या कारण बताए हैं ?

श्री राज बहादुर : अगर इस प्रश्न का संबंध प्रश्न भाग के अ से है और सीलिंग से है तो स्टेटमेंट के दूसरे पैरा में कहा गया है कि अभी इसको कायम नहीं कर रहे हैं क्योंकि राज्यों को विशेष आय की आवश्यकता है।

श्री म० ला० द्विवेदी : विवरण के दूसरे पेज पर लिखा हुआ है :

The Government of Assam have intimated that there are practical difficulties in implementing the recommendation . . . .

वहां पर माल ढोने के लिये पानी में भी काम होता है, इसलिए नहीं हो सकता है। मोटर वीहिकल्ज टैक्सेशन के अन्तर्गत क्या मोटर बोट्स भी आती हैं, यदि नहीं तो इस में असम सरकार को क्यों दिक्कत हो रही है ?

श्री राज बहादुर: इसके दो भाग हैं। एक तो यह है कि सारे जो मोटर वीहिकल्ज पर टैक्सिस हैं, उनको इकट्ठा किया जाए और दूसरा यह है कि एक ही अधिकारी के द्वारा उनको लिया जाए। इस विषय में रोड पर जो अधिकारी काम में लाया जाता है वही अधिकारी बोट्स पर काम में नहीं लाया जा सकता है, इसलिए उन्होंने अपनी व्यवहारिक कठिनाई बताई है।

Shri P. N. Kayal: Would the Government consider the proposal that the tax-payers can pay their taxes by post and do not personally have to go to the offices?

Shri Raj Bahadur: Motor vehicles are taxed in many ways—by the Central Government through certain excise and customs duties, by the State Governments, such as motor vehicles tax, etc. and by the local bodies also. I do not think that all these can be paid by post.

Dr. L. M. Singhvi: What efforts are being made to reduce the taxes on transport vehicles in order that they may compete with other means of transport available in the country? Is the Government satisfied with the measures of rationalisation listed in the statement laid on the Table of the House or is there anything else contemplated?

Shri Raj Bahadur: The quantum of tax to be imposed on motor vehicles is entirely within the power and authority under the Constitution vested in the States, not with the Centre. We have been trying to persuade them to rationalise with a view to minimise the burden of taxation on motor vehicles. So far as satisfaction of the outcome is concerned, we are yet making efforts and we will try to do whatever we can.

मेवों का आयात

+

*१२१६. { श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री ब्रजराज सिंह :

क्या सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में कितने सहकारी स्टोरों को १९६२–६३ तथा १९६३–६४ में मेवों के आयात के लिये लाइसेंस दिए गये हैं ;

(ख) दो वर्षों में इन सहकारी स्टोरों ने कितनी खजूर तथा बादाम गिरी का आयात किया ;

(ग) ये स्टोर सब खर्च लगाकर मेवे किन मूल्यों पर बेच रहे हैं; और

(घ) क्या यह सच है कि ये स्टोर मेवे बेच कर अधिक मुनाफा कमा रहे हैं ?

सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ब० स० मूर्ति) : (क) दिल्ली में किसी भी सहकारी स्टोर को सूखे मेवे के आयात के लिये लाइसेंस नहीं दिया गया था। तथापि, राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लि०, नई दिल्ली को इस कार्य के लिए १९६२–६३ में एक लाइसेंस दिया गया था और वस्तुएं १९६३–६४ में आयात की गई थीं।

(ख) व (ग). एक विवरण लोक-सभा पटल पर रखा जाता है।

(घ) जी नहीं। संघ को केवल २ प्रतिशत लाभ के रूप में लेने की अनुमति दी गई थी।

[(a) No cooperative store in Delhi had been given a licence for import of dry fruits. However, the National Agricultural Cooperative Marketing Federation Ltd., New Delhi, was given a licence for this purpose in the year 1962-63 and goods were imported in 1963-64.

(b) and (c). A statement is laid on the Table of the Lok Sabha.

(d) No, Sir. The Federation was allowed only a margin of 2 per cent as profit.].

विवरण

प्रश्न का (ख) भाग	(दो वर्षों में इन सहकारी स्टोरों ने कितनी खजूर तथा बादाम गिरी का आयात किया)
मद	राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ द्वारा १९६३–६४ (जनवरी १९६४ के अंत तक) में आयात की गई खजूर और बादाम गिरी।
(१) गीले खजूर	५२५०.०० टोन्स
(२) सूखे खजूर	१५६.९० टोन्स
(३) बादाम गिरी	१८.५० टोन्स

प्रश्न का (ग) भाग	(ये स्टोर सब खर्च लगा कर मेवे किन मूल्यों पर बेच रहे हैं)
मद	राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ के सब खर्च लगा कर बेचने के मूल्य।
	प्रति टोन
(१) गीले खजूर	रु० ५५५.६०